Just Transition Research Fellowship – IIT Kanpur and Climate Trends

जस्ट ट्रांजीशन के बारे में क्या सोचते हैं मज़दूर यूनियन

Research fellow – मनोज कुमार सिंह

Place - झारखंड

मजदूर संगठनों के साथ चर्चा करते हुए. फोटो: मनोज सिंह

1. प्रस्तावना

ग्लासगो पर्यावरण सम्मेलन के बाद विश्व के सभी देशों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने का निर्णय लिया है. इस मुद्दे को लेकर गंभीर देशों ने बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए एक टाइम लाइन तय किया है. सभी देशों ने अपने-अपने हिसाब से काम करने का निर्णय लिया. भारत सरकार ने भी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कई एजेंडा सेट किया. भारत ने भी तय किया है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा.

भारत ने अब तक तय नहीं किया है कि कब तक कोयला उत्पादन को कम किया जायेगा. फिर यह निश्चित है कि 2030 तक भारत में कोयले का उत्पादन लगभग डेढ़ बिलियन टन तक पहुंच जायेगा. हालांकि भारत का रुख फॉसिल फ्यूल फेज आउट की तरफ भी साफ है. भारत को पता है कि कुछ दशकों के बाद इसका इस्तेमाल कम

होगा. उस समय जो लोग फॉसिल फ्यूल इको सिस्टम से जुड़े हैं, उनके लिए नये काम के साधन क्या होंगे और उसके लिए अभी से क्या काम होगा, इस मुद्दे पर अभी से बातचीत शुरू हो गयी है.

अंतर मंत्रालय कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी भी 75 फीसदी से अधिक ऊर्जा उत्पादन का स्त्रोत कोयला ही है. भारत में आने वाले 100 से अधिक साल का कोयला खोजा जा चुका है. इसका खनन होना बाकी है. अाज भी यह चर्चा नीति निर्माता या इस विषय से सीधे जुड़े उच्च स्तर के लोगों तक ही है. अब धीरे-धीरे इसे जमीन पर उतारने की तैयारी हो रही है.

जब यह चर्चा होने लगी तो लगा कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं, जहां की आजीविका या आय का बड़ा साधन कोयला है. इसमें झारखंड भी एक राज्य है. जहां की आबादी सवा तीन करोड़ से अधिक है. यहां के 24 में से 12 जिलों (रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, पलामू, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा) में कोयला उत्पादन होता है. कोल इंडिया की तीन कंपनियां (सीसीएल, बीसीसीएल और इसीएल) यहां खनन करती है. एक कोयला पर रिसर्च और प्लानिंग करने वाली कोल इंडिया की कंपनी कोल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीअाइ) है. तीनों खनन कंपनियों के कुल 164 खदान अभी चल रहे हैं. इसमें इसीएल के 17, बीसीसीएल के 98 तथा सीसीएल के 49 खदान हैं. इसके अतिरिक्त टाटा और एनटीपीसी का भी अपना कोलियरी है. केवल कोल इंडिया की इन तीनों कंपनियों में 85000 कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं. एक जनवरी 2023 के कोल इंडिया के आकड़े के अनुसार बीसीसीएल में 37585, सीसीएल में 35239 तथा सीएमपीडीआइ में 2886 अधिकारी और कर्मचारी हैं. इसके अतिरिक्त करीब 10 हजार कर्मचारी और अधिकारी इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (इसीएल) के झारखंड के खदान में काम करते हैं. करीब इतनी ही संख्या में ठेका श्रमिक हैं.

इसी तरह एनटीपीसी और टाटा के कोलियरी में भी एक हजार से अधिक लोग काम करते हैं. यह वैसे लोग हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से कोयला कंपनियों से जुड़े हैं. इस कारोबार से अप्रत्यक्ष लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं. झारखंड में कुछ जिले (धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग आदि) तो ऐसे हैं, जहां की पूरी व्यवस्था कोयला पर आधारित है.

2022 में झारखंड को कोयले से मिला था करीब 10339.44 करोड़ रुपया

झारखंड खनन बहुल राज्य है. यहां कई तरह के मिनरल्स पाये जाते हैं. कोयला इसमें एक महत्वपूर्ण मिनरल्स है. इससे राज्य को बड़ी आय होती है.2021- 2022 में राज्य सरकार को कोयले से करीब 10339.44 करोड़ (कोल इंडिया का आकड़ा) रुपये कई स्त्रातों से राजस्व प्राप्त हुआ था. फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि झारखंड को 2022 में रॉयल्टी से 3028.27, एनएमइटी (सीएफ) से 60.53 डीएमएफटी से 914.01, सेल्स टैक्स

से 1.17, सीजीएसटी में 492.98, एसजीएसटी में 492.98 तथा आइजीएसटी में 7.15 करोड़ रुपये मिला था. इसके अतिरिक्त जीएससी कंपेंसेशन में 4668.37, कोल सेस में 13.55, सेंट्रल सेल्स टैक्स में 0.19 व अन्य मद में 660.26 करोड़ रुपये मिला था.

झारखंड से अगर कोयला का खनन समाप्त कर दिया जायेगा तो राजस्व की बड़ी क्षति होगी. इसके नुकसान की भरपाई एक बड़ी चुनौती होगी. इसके अतिरिक्त झारखंड में काम करने वाले करीब 85 हजार कर्मियों का वेतन और भत्ता भी यहीं खर्च होता है. अगर इनको बाजार से हटा दिया जाये, तो बड़ी संख्या में राजस्व की क्षति राज्य को होगी.

राज्य के कई जिलों का कारोबार ही कोयला कर्मियों पर आधारित है. कोयला कंपनियों इसके अतिरिक्त अपनी आय से करीब 70 करोड़ रुपये सीएसआर पर खर्च करती है. यह पैसा कोल कंपनियों के कमांड एरिया में स्वास्थ्य सुविधा, पानी आपूर्ति, पोषण और स्वच्छता के साथ-साथ शिक्षा, आजीविका के क्षेत्र में खर्च करती है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और खेलों के विकास भी कोयला कंपनियां खर्च कर रही है. कोयला उत्पादन खत्म करना एक चुनौती होगी.

इसके लिए अब राज्य सरकार ने सोचना शुरू कर दिया है. इसके लिए राज्य स्तर पर एक टॉस्क फोर्स बनाया गया है. कोयले या अन्य खनन कार्य को समाप्त या कम करने होनेवाली परेशानियों से निपटने में क्या परेशानी होगी इस पर रिपोर्ट तैयार होगा. इसके लिए राज्य सरकार ने पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) ए के रस्तोगी की अध्यक्षता वाली जस्ट ट्रांजिशन पर एक कमेटी बनायी गयी है. कमेटी अगले दो साल तक इससे पड़ने वाले प्रभाव तथा प्रभाव को दूर करने के उपाय पर मंथन करेगी. इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स से भी बात कर रही है.

वहीं कोयला कंपनियों ने भी इसको लेकर काम करना शुरू कर दिया है. जस्ट ट्रांजिशन को लेकर कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया स्तर पर कमेटियां बनायी गयी है. कमेटियों में केवल अधिकारियों को रखा गया है. वैसे, झारखंड में पड़ने वाली कंपनियों की कमेटी इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं दिखती है. कमेटी को हर माह अपनी रिपोर्ट देनी है. लेकिन, बैठक भी नहीं होती है.

कोल इंडिया के कंपनियों के जस्ट ट्रांजिशन कमेटी में मजदूर प्रतिनिधियों को नहीं रखने को लेकर यूनियनों में नाराजगी है. यूनियन ने इसको लेकर कोल इंडिया चेयरमैन को पत्र भी लिखा है. इसमें कोल इंडिया में मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले मान्यता प्राप्त चारों यूनियनों (एटक, सीटू, एचएमएस और बीएमएस) के प्रतिनिधियों ने भी हस्ताक्षर किया है. उनका भी मानना है कि एक तरफा निर्णय कोयला उद्योग को बड़ी संकट में डाल सकता है. मजदूर प्रतिनिधि भी जस्ट ट्रांजिशन के इस अभियान में हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं.

कोयला उद्योग में मजदूर संगठनों की स्थिति

वेतन समझौता हो, सुरक्षा का मुद्दा हो या सुविधा; बिना मजदूर संगठनों की सहमति के तय नहीं होता है. कई स्तर पर कोल इंडिया प्रबंधन और मजदूर प्रतिनिधियों की संयुक्त कमेटियां है. कोल इंडिया में कोयला मंत्रालय ने देश की पांच केंद्रीय श्रमिक संगठनों (भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर सभा, एटक, सीटू और इंटक) को मान्यता दे रखा है. अभी कानूनी विवाद के कारण कोल इंडिया ने इंटक को किसी भी कमेटी में स्थान नहीं दिया है. यही कारण है कि बिना मजदूरों की सहमति के आज भी कोयला उद्योग में प्रबंधन कोई बड़ी निर्णय नहीं ले पाता है. इसके लिए कोल इंडिया की सभी कंपनियों में पिट स्तर (सबसे निचली इकाई) से लेकर कोल इंडिया स्तर तक की एक कमेटी है, जिसमें मजदूर यूनियन के साथ-साथ प्रबंधन के लोग भी रहते हैं. इस कारण जस्ट ट्रांजिशन (न्यायपूर्ण बदलाव) के लिए मजदूर संगठनों को विश्वास में लेना जरूरी होगी. इनको विश्वास में लिये बिना कोई भी प्रयास कोयला उद्योग को समय से पहले नुकसान पहुंचा सकता है. इससे देश को बड़ा ऊर्जा संकट झेलना पड़ सकता है.

2. अध्ययन में शामिल लोग

जस्ट ट्रांजिशन के मुद्दे पर सीसीएल के विभिन्न एरिया में संचालित मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से बात की गयी. मजदूर संगठनों से यह समझने की कोशिश की गयी कि क्या उनको पता है कि एक समय आयेगा जब कोयला उत्पादन बंद हो जायेगा. इससे क्या असर पड़ेगा ? बातचीत (करीब 50 मजदूर प्रतिनिधियों, सीटू-10, एटक-15, इंटक-5, एचएमएस-15 व बीएमएस-5) दौरान एरिया (जहां खनन होता है) से लेकर मुख्यालय स्तर के मजदूर नेताओं से बात की गयी. मजदूर यूनियनों में मुख्यत: चार तरह के मजदूरों का चयन अध्ययन के दौरान किया गया. इसमें एक ऐसे मजदूर यूनियन नेता थे, जो मजदूरों के मुद्दों को लेकर कोल इंडिया की कमेटियों में अपनी बात रखते हैं. इसमें ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी ऑन कोल इंडस्ट्रिज (जेबीसीसीआइ) वेलफेयर बोर्ड, ऐपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी), नन एक्जीक्युटिव सदस्य सीएमपीएफ बोर्ड थे.

इसके अतिरिक्त कंपनी स्तर पर विभिन्न कमेटियों में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले मजदूरों को शामिल किया गया. इसके अतिरिक्त एरिया (कंपनी के सबसे नीचे स्तर) के मजदूर प्रतिनिधियों को भी बातचीत में शामिल किया गया. वैसे इलाकों का अध्ययन में चयन किया गया जहां पुरनी खदानें हैं, जहां कोयला खनन बहुत कम हो गया है. इसमें बोकारो जिला में पड़ने वाला ढोरी, कथारा, फुसरो का इलाका है. इसके अतिरिक्त बरकासयाल, सौंदा, अरगड्डा आदि एरिया के मजदूर प्रतिनिधियों को भी बातचीत में शामिल किया गया. जहां खनन का काम बंद कर दिया गया है. वहां पहले से चली आ रही खदानें बंद हो गयी है.

कुछ वैसे इलाकों में भी मजदूर प्रतिनिधियों से बात की गयी, जहां नयी खदान अभी भी वर्षों से चालू है. तीसरे में वैसे खनन क्षेत्र के मजदूर प्रतिनिधियों को बातचीत में रखा गया, जहां पहली बार कोयला खनन हो रहा है. हाल के कुछ वर्षों में पूरे इलाके की समृद्धि का बड़ा कारण बना हुआ है. इसमें आम्रपाली, चंद्रगुप्त, खलारी, पिपरवार एनके और डकरा एरिया को रखा गया. इसके अतिरिक्त कुछ वैसे मजदूर प्रतिनिधियों से भी बात गयी जो मुख्यालय (रांची) में हैं. यहां से क्षेत्र के मजदूर प्रतिनिधियों के साथ समन्वय का काम करते हैं.इसमें करीब 30 मजदूर प्रतिनिधि एरिया का मुख्यालय के थे. इसमें वैसे मजदूर शामिल थे, जो किसी ना किसी नीचे स्तर के कमेटी में मजदूरों के प्रतिनिधि हैं. इसके अतिरिक्त 12 कंपनी स्तर के मुख्यालय में मजदूरों के प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन सदस्यों को रखा गया. आठ वैसे मजदूर प्रतिनिधियों से भी बात की गयी, जो कोल इंडिया स्तर पर मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं. उनके वेतन समझौते या सुविधा पर बात करते हैं.

सीसीएल का आम्रपाली खदान. फोटो: मनोज सिंह

3. खोज और चर्चा

3.1. कोयले के बिना जीवन संभव नहीं

कोल इंडिया स्तर के जितने भी प्रतिनिधियों से बात की गयी, उनको यह जानकारी थी कि जस्ट ट्रांजिशन जैसी कोई बात चल रही है. उनका कहना था कि कई बार मीटिंग में यह बात बतायी गया है कि कोयला से होने वाले प्रदूषण के कारण उत्पादन कम करना है. लेकिन, इसमें कई बड़े नेताओं का मानना है कि यह एक बड़ी साजिश है. इसका शिकार मजदूरों को बनाया जायेगा. वैसे कोयला उत्पादन खत्म या कम करने की संभावना नहीं है. यह आसान भी नहीं है. अगर ऐसा हुआ या मजबूरी में करने का प्रयास हुआ तो कोयला उद्योग का सबसे बड़ा आंदोलन भी हो सकता है. क्योंकि झारखंड में करीब 12 जिलों में कोयला खनन का काम होता है. यह सीधे इससे प्रभावित होंगे. बड़े मजदूर नेता भी अभी विकल्प पर बात नहीं करना चाहते हैं. वैसे वह चाहते हैं कि अगर कोयला कंपनियों कुछ सोच रही है, या आगे की कोई योजना पर काम कर रही है, तो उनको भी बताया जाना चाहिए. जस्ट ट्रांजिशन को लेकर बनने वाली कमेटियों में उनको भी स्थान मिलना चाहिए.

वहीं कंपनी स्तर पर मजदूर का नेतृत्व करने वाले मजदूर नेताओं को इस विषय को लेकर बहुत ज्ञान नहीं है. कुछ तो कहते हैं कि हां सुनने में आ रहा है. लेकिन, कुछ नेताओं का कहना है कि यह सब आइवाश है. निकट भविष्य में यह संभव नहीं है. कोयले की मांग तो दिनों दिन बढ़ रही है. लेकिन, यह भी कहना है कि अगर कोयला कंपनियों को बंद करने की जबरन कोशिश हुई, तो आंदोलन तय है. इसको कोई रोक नहीं सकता है. मजदूरों के सामने अभी कोयला को छोड़कर कोई विकल्प नहीं है. मजदूर नेता इसको आसानी से नहीं लेने वाले हैं. उनका मानना है कि कोयले का विकल्प कुछ नहीं हो सकता है. कहते हैं कि जो जमीन पर हैं, उनको पता है कि पूरा का पूरा इलाका बंजर हो जायेगा.

एरिया स्तर मजदूरों की बात रखने वाले नेताओं की सोच भी कुछ ऐसी ही है. वह भी कहते हैं कि अगर बंद करने की साजिश हुई तो व्यापक आंदोलन होगा. जहां हाल में खनन का काम शुरु हुआ है, जहां लंबे समय तक खनन की संभावना है, वहां के मजदूर नेता इसका विकल्प सोचने को भी तैयार नहीं है. उनका कहना है कि अभी लंबे तक यह यहां से कोयला निकलेगा. यह मजदूरों को परेशान करने की साजिश है. अगर मजदूरों के साथ जबरन किया गया तो एक जन आंदोलन खड़ा हो जायेगा. क्योंकि इससे केवल वहां काम करने वाले ही नहीं, आसपास की आबादी भी प्रभावित है. रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं हो सकता है.

वहीं ढोरी, फुसरो, कथारा आदि इलाकों के कुछ मजदूर नेताओं का कहना था कि सरकार अगर विकल्प की बात कर रही है, तो इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए. केवल एक तरफा निर्णय नहीं होनी चाहिए. जो काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा यह बताना होगा. वैसे उनका यह भी कहना है कि प्रबंधन जो गलती कर रही, उसका खामियाजा

मजदूरों को भुगतना पड़ेगा. प्रबंधन ने वायु प्रदूषण रोकने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया. यही कारण है कि खदान बंद करने की बात होनी लगी है.

बातचीत के दौरान 90 फीसदी से अधिक (एरिया स्तर के मजदूर प्रतिनिधि) का कहना था कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार कोयले का खनन कम करने वाली है. वह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है. उनका कहना था कि इस इलाके में कोयला के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती है. वहीं मात्र 10 फीसदी मजदूर प्रतिनिधियों का कहना था कि इस मुद्दे पर बात की जा सकती है. पहले विकल्प बताना होगा. लेकिन, 10 फीसदी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि कोयला खनन बंद होगा. उनका कहना था कि अगर बात प्रदूषण की है तो पहले खनन प्रक्रिया में सुधार करे. कोल इंडिया प्रबंधन अपनी गलती का खामियाजा मजदूरों को नहीं भुगतने दें.

इस कारण मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों का मानना है कि कोयला उत्पादन कम करने के किसी भी प्रयास को बिना मजदूरों की सहमति के नहीं करना उनको एक रोड मैप बताना चाहिए कि आगे कोल इंडिया प्रबंधन या कोयला कंपनियों क्या करने वाली अगर खदान बंद करना हो या कम करना हो तो उपलब्ध मैन पावर के लिए क्या-क्या विकल्प हो सकता है. इस तरह साझा प्रयास से ही रास्ता निकल सकता है और बातचीत बहुत जरूरी है, तभी सब एक साथ इस पर आगे बढ़ सकते हैं.

3.2. वीरान हो गया है पलामू का रुर

मजदूरों का डर कुछ हद तक गलत भी नहीं. उदाहरण के तौर पर, कभी पलामू का रुर (जर्मनी का खनन इलाका) कहा जाने वाला राजहरा एरिया आज वीरान हो गया है. राजहरा कोलियरी के आसपास के इलाका में रोजगार का कोई स्थायी साधन भी नहीं है. राजहरा कोलियरी का सरकारी आवास जर्जर हो गया है. यह जानवरों के रहने का स्थान हो गया है. कंपनी की जमीन पर कब्जा हो रहा है.

असल में खदान बिना किसी क्लोजर प्लान के क्लोज (बंद) है. इसका असर हुआ कि कभी लोडिंग का काम करने वाले दैनिक मजदूर और उनके परिवार का पलायन हो गया है. इस कोलियरी से कभी आसपास के दो दर्जन गांव (करीब 20 हजार आबादी) गुलजार थी. अब ना इस इलाके के चौक-चौराहे में रौनक है, ना बाजार में. बिजली, पानी, स्कूल सभी की व्यवस्था जर्जर है. स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर दो कमरे का एक अस्पताल है. जहां सीसीएल के डॉक्टर कभी-कभी आते हैं. यहां महाप्रबंधक का पद भी प्रभार में है. स्टॉफ ऑफिसर पर्सनल (एसओपी) का पदस्थापन ही नहीं है.

यह खदान 2012 से बंद है. सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल) के राजहरा खदान (पलामू) से पिछले 10 साल से पानी निकाला जा रहा है. यहां तीनों शिफ्ट में पानी निकाला जाता है. खदान से पानी निकलेगा, तभी कोयला निकल पायेगा. पानी खत्म करने के लिए कंपनी का प्रयास अभी भी जारी है. अब तक कंपनी करोड़ों लीटर पानी निकाल चुकी है. इस पर करोड़ों रुपये खर्च भी हो गया है. लेकिन, खुदाई नहीं हो पा रहा है. कंपनी प्रबंधन को अभी भी उम्मीद है कि पानी निकल जाने के बाद खुदाई शुरू हो जायेगा. जब तक पानी निकलता है, खुदाई की तैयारी होती है, फिर बारिश हो जाती है. इसके अतिरिक्त बगल की नदी से पानी भी पसीज कर खदान को भर देता है. कंपनी मुख्यालय से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित खदान 2012 से बंद है. इसी समय खदान में पानी घुस गया है. इसके बाद से यहां कोयला निकलना बंद हो गया है. कहने को तो यहां सीसीएल का खनन क्षेत्र है, लेकिन गतिविधि के नाम पर मात्र पानी निकलाना ही है. बीच-बीच में दूसरी जगह खनन करने के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रयास होता है. यह काम भी लंबे समय से चल रहा है. कंपनी को सफलता नहीं मिली है. बिना किसी योजना के खदान बंद हो जाने का असर पूरे इलाके पर दिखता है.

3.3. खत्म हो गयी है इलाके की रौनक

राजहरा खदान देश के सबसे पुराने खदान में से एक है. 1844 से इस खदान से खनन का काम हो रहा है. बंगाल कोल कंपनी इसका संचालन करती थी. 1975 में कोयला कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद से यह सीसीएल के पास है. सीसीएल ने यहां से 2012 तक कोयला निकाला है. वहां के पुराने कर्मचारी बताते हैं कि एक समय यहां से एक लाख टन तक कोयला निकला है. 500 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी यहां थे. डालटनगंज मुख्यालय से ज्यादा रौनक इस इलाके में रहती थी. हर दिन एक-एक सौ ट्रक कोयला ढुलाई के लगता था. आसपास के 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलता था.

80 के दशक में यहां परदे पर फिल्म चलायी जाती थी. अब तो आसपास के लोगों के पास केबल का पैसा देना भी मुश्किल है. अब मात्र 102 के आसपास के कर्मचारी बचे हैं. उसमें भी ज्यादतर सरकारी आवास छोड़कर डालटनगंज से आना जाना करते हैं. कर्मचारियों का कहना है कि खनन नहीं होने के कारण बहुत काम भी नहीं है.

3.4. 58 एकड़ जमीन पर है विवाद

सीसीएल 58 एकड़ जमीन पर खुदाई करना चाहता है. इस जमीन को लेकर रैयत और कंपनी के बीच विवाद है. कंपनी ने इस विवाद को सलटाने के लिए कई बार जिला प्रशासन से आग्रह किया है. लेकिन, यह अब तक नहीं सलटा है. रैयत इस जमीन से हटना नहीं चाहते हैं. जिला प्रशासन ने जमीन चिन्हित कर सीसीएल को नहीं दिया है.

रैयतों का कहना है कि उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है. वहीं, सीसीएल प्रबंधन का कहना है कि मुआवजा लेने के बाद भी कई लोग जमीन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं. अगर यह जमीन मिल जायेगा तो अगले सात साल तक कोयला निकाला जा सकता है.

स्मोकलेस कोयला है यहां का - सीसीएल प्रबंधन का कहना है कि यहां के कोयला की गुणवत्ता अच्छी है. इसकी बाजार में मांग बहुत अधिक है. जब यहां से उत्पादन होता था, इसकी कीमत अच्छी मिलती था. अभी भी कोयला निकाला जायेगा, तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी.

3.5. नहीं मिल रहा सीएसआर का लाभ

चूंकि यहां खनन नहीं हो रहा है, इस कारण कंपनी सीएसआर का पैसा नहीं खर्च कर पा रही है. खदान संचालन के समय आसपास के लोगों के लिए कई सीएसआर के काम होते थे. कंपनी का साइडिंग भी अब निजी कंपनियों के इस्तेमाल में आ रहा है. यहां एक चिकित्सक पदस्थापित हैं, वे आते हैं. काम करने वाले कर्मियों की जांच होती है. यहां प्रोजेक्ट ऑफिसर का पदस्थापन नहीं है.

वर्षों से पानी निकल रहा है राजहरा के कोयला खदान से. फोटो: मनोज सिंह

स्थानीय पत्रकार अजीत कुमार मिश्र बताते हैं कि इस खदान का दो-दो बार चालू करने की कोशिश की गयी. असल में इस कोशिश में गंभीरता नहीं थी. राजनीतिक उद्देश्य से इसे लोगों को आश्वासन देने के लिए ऐसा किया गया. इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, कंपनी के प्रति लोगों की नाराजगी ज्यादा बढ़ गयी. असल में इसको बंद करने से पहले किसी तरह का कोई संकेत नहीं था. इस कारण रातो रात अचानक खदान से कोयला निकलना बंद हो

गया. ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गया है. यहां से मैनुअल लोडिंग था. इस कारण यहां काफी लोगों को रोजगार मिलता था. एक समय में कंपनी में एक ट्रेड यूनियन नेता ने 315 लोगों को नौकरी लगायी थी. जिनको नौकरी लगायी वे संपन्न या मध्यम वर्गीय परिवार से थे. वे काम करने आते तो जरूरत थे, लेकिन उनके बदले में मजदूर लोडिंग का काम करते थे. वे अपनी कमाई से इन मजदूरों को पैसा देते थे. यहां बिहार और यूपी के व्यापारी कोराबार करने आते थे. दोनों राज्यों की सीमा के करीब होने के कारण यहां की रौनक देखते बनती थी. आज तो लोग इस इलाके को पूछते भी नहीं है. कंपनी के कर्मी भी केवल कोरम पूरा करने के लिए आते हैं. हाजिरी लगाकर इधर-उधर धूमते रहते हैं.

4. कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत के अंश एवं निष्कर्ष

4.1. कोयला केवल प्रबंधन नहीं, जनता का भी मुद्दा

डीडी रामानंदन, सदस्य, जेबीसीसीआइ (सीटू)

जस्ट ट्रांजिशन को लेकर कोल इंडिया में भी चर्चा हो रही है. कई दौर की मीटिंग भी हुई है. अनौपचारिक रूप से कई मीटिंग में यूनियनों को शामिल किया गया है. सभी कंपनियों ने जस्ट ट्रांजिशन को लेकर एक कमेटी भी बनायी है. इसका हम लोगों ने विरोध किया है. कहा है कि बिना मजदूरों की सहमति के कोयला उद्योग में बदलाव का प्रयास गलत होगा. अभी कोल इंडिया के सिवा कोई विकल्प नहीं है. निजी कंपनियों को कोयला निकालने में अभी समय लगेगा. कोल इंडिया देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है. जस्ट ट्रांजिशन के नाम पर अगर कोल इंडिया की कंपनियों को बंद करने का प्रयास हुआ तो विशेषकर झारखंड को बड़ा नुकसान होगा. यहां की सामाजिक पृष्टभूमि में कोयला है. इसका आर्थिक लाभ राज्य को हो रहा है. यह करीब एक दर्जन जिलों के लोगों को रोजगार का साधन है. इस लिए ठोस उपाय करना जरूरी है .

4.2. जस्ट ट्रांजिशन अंतरराष्ट्रीय जुमला

लखन लाल महतो, सदस्य जेबीसीसीआइ (एटक)

विश्व बैंक और कुछ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्था का दिया हुआ एक जुमला है. भारत जैसे विकासशील देश में बिना कोयले के ऊर्जा की जरूरत पूरा करना फिलहाल संभव नहीं है. कोल इंडिया कई दिशा में हाथ-पांव मार रही है. इससे कुछ होने वाला नहीं है. अगर इस दिशा में बिना कोई ठोस प्लानिंग के कुछ करने की कोशिश हुई तो परिणाम अच्छा नहीं होगा. बड़ी संख्या में बेरोजगारी फैलेगी. जो कोयला निकालने में एक्सपर्ट है, उनको किसी दूसरे काम में लगाने के लिए व्यापक प्लानिंग की जरूरत है. झारखंड जैसे राज्य में कोयला आजीविका का सबसे बड़ा साधन है. सबसे अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी इसी सेक्टर में है. इस सेक्टर को छेड़ने का परिणाम अच्छा नहीं होगा. इस कारण एक बड़ी रणनीति के साथ काम करना होगा.

4.3. कोयला उत्पादन घटाने के बजाए, क्लीन कोल पर बात करें प्रबंधन

राजेश सिंह, जेबीसीसीआइ सदस्य, कोल इंडिया

जेबीसीसीआइ की बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन ने कहा था कि कोल इंडिया को अब सौर ऊर्जा पर भी फोकस कराना है. नीचे स्तर पर भी बात करने की कोशिश हो रही है. लेकिन, यूनियन के रोल पर बात नहीं हो रही है. यूनियन को अंधेरे में रखने का बुरा नतीजा हो सकता है. कोयला खत्म या कम करना जरूरी है या क्लीन कोल जरूरी है. इस पर तो बात होनी चाहिए. बिना प्रदूषण के कोयला कैसे निकाले, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं. देश में जितना कोयले का स्टॉक है, उसका 50 फीसदी भी अभी नहीं निकला है. जहां जमीन के अंदर इतना संसाधन है, वहां इसके विकल्प पर बात करने का समय अभी नहीं है. कोल इंडिया प्रबंधन या भारत सरकार को अपनी नियत साफ रखना होगा. तभी बंद होने के बाद की स्थिति पर चर्चा हो सकती है. यूनियन खदान बंद करने के पक्ष में कभी नहीं रहेगी. कोयला उद्योग के निजीकरण का प्रयास हो रहा है. 1975 में कोल इंडिया में करीब 7.5 लाख मजदूर थे. आज 2.35 लाख के आसपास हैं. इसके स्थान पर ठेका श्रमिक लाये गये हैं. यूनियन श्रमिकों का अधिकार समाप्त नहीं हो, इस कारण ठेका मजदूरों को समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रही है. हाइपावर कमेटी की अनुशंसा इमानदारी से लागू करने की बात कह रही है.

4.4. आंदोलन को सिवा कोई रास्ता नहीं

राजीव रंजन सिंह, भारतीय मजदूर संघ, सदस्य बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कोल इंडिया (कर्मचारी)

खदान ही कोयला मजदूरों का जीवन है. कोयला उत्पादन कम या खत्म करने की बात होती है, तो मजदूरों के बारे में सोचना होगा. कोयला खनन धीरे-धीरे कम करने की योजना, शुरुआती बात है. कोयला खदान बंद ही नहीं होगा. अगर बंद होगा तो यूनियन किसी हद तक जा सकती है. इससे पहले तो बंद खदानों को निजी कंपनियों को दिया जा रहा है. ऑक्शन हो रहा है. इसका असर आने वाले कुछ वर्षों में दिखेगा. निजी कंपनियों का कोयला सस्ता होगा. कोल इंडिया को अपने उत्पाद बेचने में दिक्कत होगी. क्योंकि निजी कंपनियों का मैनपावर पर होने वाला खर्च कम होगा. इस कारण उत्पादन लागत भी कम होगी. अब जस्ट ट्रांजिशन नाम का एक विषय सामने आ रहा है. पता चला है कि कोयला खनन कम या खत्म करने की कोई योजना बन रही है. इसमें यूनियन की भूमिका प्रभावी होगी. प्रबंधन को यूनियन की जानकारी के बिना ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जिससे मजदूरों के हितों का नुकसान हो. बहुत मुश्किल होगा कहना, क्योंकि पूरा झारखंड खत्म हो जायेगा. वर्तमान स्थिति में कोयला श्रमिकों को विकल्प देना आसान नहीं है. अभी कोई रास्ता नहीं है.

4.5. अगर ऐसा हुआ तो सड़क पर उतरना होगा

बिंध्याचल बेदिया, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन (एटक)

लगभग 30-35 साल से कोयला मजदूरों के लिए यूनियन चला रहे बिंध्याचल बेदिया का मानना है कि पिछले वर्षों में कई खदान बंद हुए हैं. वहां वीरानी छा जाती है. अगर कोयला खदान बंद करने की कोशिश की गयी तो प्रबंधन से बात होगी. यह समझ में नहीं आ रहा है कि कोयला खत्म करके क्या करेंगे. इसका कोई विकल्प है नहीं. इससे सस्ता बिजली भी नहीं पायेगा. खदान बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी, इसके लिए यूनियन तो किसी हद तक जा सकती है. यह केवल यूनियन के लिए नहीं, मजदूरों के जीवन-मरण का सवाल है. अभी यह कोयला उद्योग को निजी हाथों में बेचने की साजिश है. कोयला उद्योग में ठेका मजदूरों का शोषण हो रहा है. कोयला उत्पादन कम या खत्म करने का असर बहुत व्यापक पैमाने पर होगा. देश के कई जिलों की आर्थिक स्थित खराब हो जायेगी. मेरा मानना है कि अभी फिलहाल 10-20 साल तक कोयला बंद नहीं होगा. कोयला बंद होगा तो कितने लोगों को रोजगार चला जायेगा.

4.6. प्रदूषण के नाम पर मजदूरों का शोषण करने की तैयारी

सुखदेव प्रसाद, जनता मजदूर संघ, सीसीएल वेलफेयर बोर्ड सदस्य

कोयला समाप्त या कम करने का व्यापक असर पड़ेगा. पूरा का पूरा इलाका ठप हो जायेगा. रोजी रोजगार का संकट हो जायेगा. केवल काम करने वाले ही नहीं विस्थापित भी परेशानी में पड़ जायेंगे. बस्ती का बस्ती खाली हो जायेगा. खदान बंद होने से पूरा इलाका विरान हो जाता है. जिस मुद्दे को लेकर खदान बंद करने की बात हो रही है. वह अधिकारियों की दी हुई समस्या है. सरकार ने क्लीन कोल के लिए कई दिशा-निर्देश दिया है. इस पर काम नहीं होता है. इसका ठिकरा अब मजदूरों पर फोड़ने की तैयारी है. रामगढ़ में ही घाटो कोलियरी है. इससे टाटा चलाती है. जाकर देख लीजिए, वहां लगेगा नहीं कि आप कोयला खदान में आ गये हैं. जब टाटा साफ-सुथरा कोयला निकाल सकता है, तो कोल इंडिया क्यों नहीं. अगर जबरन कोयला उत्पादन कम ठप करने की कोशिश हुई तो यूनियन कुछ भी कर सकती है. जस्ट्र ट्रांजिशन को लेकर अभी तक प्रबंधन ने नीचे स्तर पर कोई डिसक्शन नहीं किया है. अगर ऐसा होगा तो यूनियनों की भागीदारी जरूरी है.

4.7. कोयला कर्मियों के लिए जीवन मरण का सवाल होगा

जगरनाथ साहु, केंद्रीय सचिव, कोलफील्ड मजदूर यूनियन (एचएमएस)

कोयला कभी बंद नहीं होगा. प्रदूषण के मुद्दे को लेकर यह एक साजिश हो रही है. इस साजिश का शिकार मजदूर यूनियन कर्मियों को नहीं होने देगा. प्रदूषण कम करना प्रबंधन का काम है. देश की जरूरत कोयला के बिना पूरी

नहीं हो सकती है. पूरे देश को राज्य से कोयला जा रहा है. अगर बंद करने की कोशिश हुई तो प्रबंधन से बात होगी. यह यूनियन या कोयलाकर्मियों के जीवन-मरण का सवाल है. खदान बंद करने की साजिश का विरोध होगा. लड़ाई तेज होगी. जस्ट ट्रांजिशन को लेकर ऊपर स्तर पर कुछ हो रहा होगा. अभी मजदूरों को यह जानकारी नहीं है. अगर ऐसी कोई योजना या कमेटी बनती है, तो कर्मचारियों की भूमिका तय होनी चाहिए. कोयला उत्पादन बंद या कम करने की कोशिश हुई तो केवल श्रमिक ही नहीं, पूरा झारखंड बर्बाद हो जायेगा. यहीं की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोयले पर निर्भर है. अभी ही उत्पादन निजी कंपनियों से ज्यादा हो रहा है. कोयला की जरूरत पूरा करने के लिए यह जरूरी भी है. निजी उत्पादन का लागत कम है. यह ठीक नहीं है. क्योंकि निजी उत्पादन में लगे कर्मियों को तय मानक के अनुसार सुविधा नहीं मिल रही है. उनको सुविधा देते हुए ज्यादा उत्पादन करना चाहिए.

4.8. जस्ट ट्रांजिशन अवधारणना की नीति का शिकार बनाने का प्रयास

कमलेश सिंह, अध्यक्ष, सीसीएल शाखा जनता मजदूर संघ

झारखंड की आबोहवा में कोयला है. कोयला देश की जरूरत है. यह आजीविका का बड़ा साधन है. अब इसको लेकर खेल हो रहा है. करीब 32 साल से सीसीएल के साथ काम करने का अनुभव है. झारखंड आज भी पिछड़ा है. यहां की बहुत बड़ी आबादी की आजीविका का साधन कोयला है. यह रोजगार का सबसे बड़ा स्त्रोत है. कई जिलों में तो कोयला के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. वहां के लोगों के जीना और मरना ही कोयला है. ऐसे में एक अंतरराष्ट्रीय अवधारणा की नीति के साजिश का शिकार होने से बचाने की जरूरत है. खदानों के बंद होने का दर्द हम लोगों ने देखा है. एक खदान बंद होती है, तो पूरी व्यवस्था बदल जाती है. आबादी विरान हो जाती है. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर का रोजगार खत्म या कम हो जाता है. जस्ट ट्रांजिशन के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है. ग्रीन एनर्जी हमारी जरूरत है. इससे कोइ इनकार नहीं कर सकता है. यह मजदूरों तक ही सीमित नहीं रहेगा. एक जागरूक नागरिक के नाते प्रदूषण हमारी समस्या है. इससे निपटने के उपाय भी जरूरी हैं. मजदूर भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, लेकिन उनकी रोजी रोजगार के एवज में नहीं.

4.9. प्रदूषण प्रबंधन की गलती, दोष मजदूरों पर नहीं दें

सुजीत घोष, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन (एटक), सदस्य सीसीएल वेलफेयर बोर्ड

लगभग 1979 से कोयला उद्योग में ट्रेड यूनियन चला रहे सुजीत घोष का मानना है कि ऊर्जा का कोई विकल्प अभी देश के पास नहीं है. मजदूर संगठन का काम है, मजदूरों का आवाज उठाना. अगर मजदूरों पर कोयला उत्पादन कम या खत्म करने का असर पड़ेगा, तो यूनियन जरूर बात उठायेगी. कोयले का विकल्प आसान नहीं है. पहले ज्यादा कोयला अंडर ग्राउंड से निकलता था, तब प्रदूषण कम होता था. अब फिर ओपेन कास्ट से कोयला निकलने

लगा है. इससे प्रदूषण ज्यादा हो रहा है. अभी जो प्रदूषण हो रहा है. उसमें प्रबंधन की गलती है. कोयला निकलाने और ढुलाई का जो मानक है, उसका पालन नहीं होता है. गाड़ियां ढकी नहीं जाती है. सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं होता है. यही कारण है कि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है. यूनियन को ज्यादा से ज्यादा प्रेसर बनाने की जरूरत है. प्रदूषण कम करने को लेकर प्रबंधन पर दबाव बनायें. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें. जब व्यवस्था सुधरेगी, तो मानसिकता बदल सकती है. बिना वैकल्पिक उपाय के इस तरह का कोई भी प्रयास जोखिम भरा होगा. अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है. झारखंड में रिनुअल एनर्जी की स्थिति ठीक नहीं है. अगर कुछ जबरन करने की कोशिश हुई तो बहुत व्यापक असर पड़ेगा. बेरोजगारी बढ़ जायेगी. काम का संकट होगा. अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ेगा. देश में अभी एनर्जी खपत बढ़ रहा है. कोयला में काम करने वाले स्थायी मजदूर घट रहे हैं. भारत सरकार ने जो टाइम लाइन तय किया है, उस समय तक स्थायी मजदूर काफी कम होंगे. इस कारण उस समय विकल्प पर नहीं रहेगा. यूनियन की भूमिका तय करनी होगी. इसमें प्रबंधन की भूमिका भी तय करना होगा. मिलजुल कर ही सही रास्ता निकल सकता है.

4.10. रवींद्र कुमार मिश्रा, सीसीएल सीकेएस (बीएमएस), वेलफेयर बोर्ड सदस्य, ढोरी (बोकारो)

हाल में विश्व बैंक की टीम आयी थी. उसी टीम के लोगों से ऐसा सुने थे, कि धीरे-धीरे कोयले का उत्पादन कम करना है. वैसे मेरा मानना है कि 2070 तक कोयला उत्पादन खत्म नहीं होगा. अभी तो हमलोग कोल रिजर्व का 20 फीसदी के आसपास ही उपयोग कर पाये हैं. भारत सरकार अगर ऐसा करती है कि बड़ी आबादी पर इसका असर पड़ेगा. आसपास में कई खदान समय-समय पर बंद हुए हैं. इससे कोयला पर अप्रत्यक्ष से निर्भर आबादी ज्यादा परेशानी होती है. कोयला खदान बंद होगा. यह मान लेने की बात ही नहीं है. देश में अंधेरा छा जायेगा. अभी तक भारत सरकार की ऐसी कोई तैयारी नहीं है, जिससे कोयला खत्म करना पड़े. सीसीएल के सीएमडी अब हर बैठक में कोयला खत्म होने का बात कहते हैं. यह सुन रहे हैं. इसका विरोध होगा. यूनियन ऐसा कोई भी काम नहीं करने देगी, जिससे मजदूर प्रभावित हो. कोयला खनन को निजी हाथों में ले जाने की तैयारी पूरी है. एक-एक कर सभी कोयला कंपनियों के पैसे पर केंद्र की नजर है. भारत सरकार चाहती है कि कोल इंडिया बंद हो जाये. जस्ट ट्रांजिशन के मुद्दे पर यूनियन के शीर्ष नेतृत्व को पहल करनी चाहिए. इस तरह के किसी भी प्रयास में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए. बिना विकल्प के कोयला खत्म करना नुकसानदायक होगा. झारखंड जैसे राज्य में इसका व्यापक असर पड़ेगा. इसका अंदाज शायद कंपनी को भी नहीं है. विकल्प पर बात करने का समय अभी नहीं है. यह बंद नहीं होगा.

4.11. वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया तो, भुगतना होगा गंभीर परिणाम

श्यामल सरकार, इंटक, बेरमो एरिया

भारत सरकार ने कोयले का उत्पादन धीरे-धीरे कम करने का निर्णय लिया है. अगर बिना कोई ठोस योजना के इस पर काम हुआ तो परिणाम गंभीर हो सकता है. झारखंड जैसे राज्य में कोयला आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का बड़ा हिस्सा है. करीब-करीब आधा राज्य कोयला पर आधारित है. हाल में कोयला उत्पादन कम करने के लिए निकले शब्द जस्ट ट्रांजिशन के मुद्दे पर सीसीएल के एक निदेशक से बात हो रही थी. उनका कहना था कि कोयला आधारित पावर प्लांटों की आयु धीरे-धीरे कम होती जा रही है. 2050 तक कई पावर प्लांट सर्वे ऑफ हो जायेंगे. कोयला आधारित नया पावर प्लांट लगाने की संभावना कम है. इसके स्थान पर गैर पारंपरिक ऊर्जा (रिनुवल एनर्जी) के नये स्त्रोत विकसित होंगे. इस कारण 2040 तक कोयले का उत्पादन सर्वाधिक ऊंचाई पर होगी. इसके बाद कोयले की मांग घटनी शुरू होगी. लेकिन, कोयला कंपनियों के खदानों आसपास का इलाका आज कोयला कर्मियों से ही गुलजार रहती है. वैसे धीरे-धीरे स्थायी कोयलाकर्मियों की संख्या घट रही है, लेकिन अस्थायी की संख्या बढ़ रही है. ठेके पर काम करने वाले कर्मियों की संख्या बहुत अधिक हो गयी है. अगर सभी के सामने रोजगार का संकट हो जायेगा, तो पूरा इलाका विरान हो जायेगा. आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जायेगी. इससे बचने के लिए अभी से योजना तैयार करने की जरूरत है. विकल्प पर गंभीरता से विचार करना होगा. कैसे, कोयला वाले इलाके को जिंदा रखना है, उस पर सोचना होगा. यूनियन ने इस पर सोचना शुरू कर दिया है. प्रबंधन पर दबाव बना रहा है. अगर यूनियन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो मजदूरों के साथ धोखा होगा. यह मामला केवल कर्मियों का नहीं है. यह आंदोलन केवल मजदूर तक सीमित नहीं होगी. यह जन आंदोलन बनेगा. क्योंकि इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, वैध और अवैध रूप से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी है.

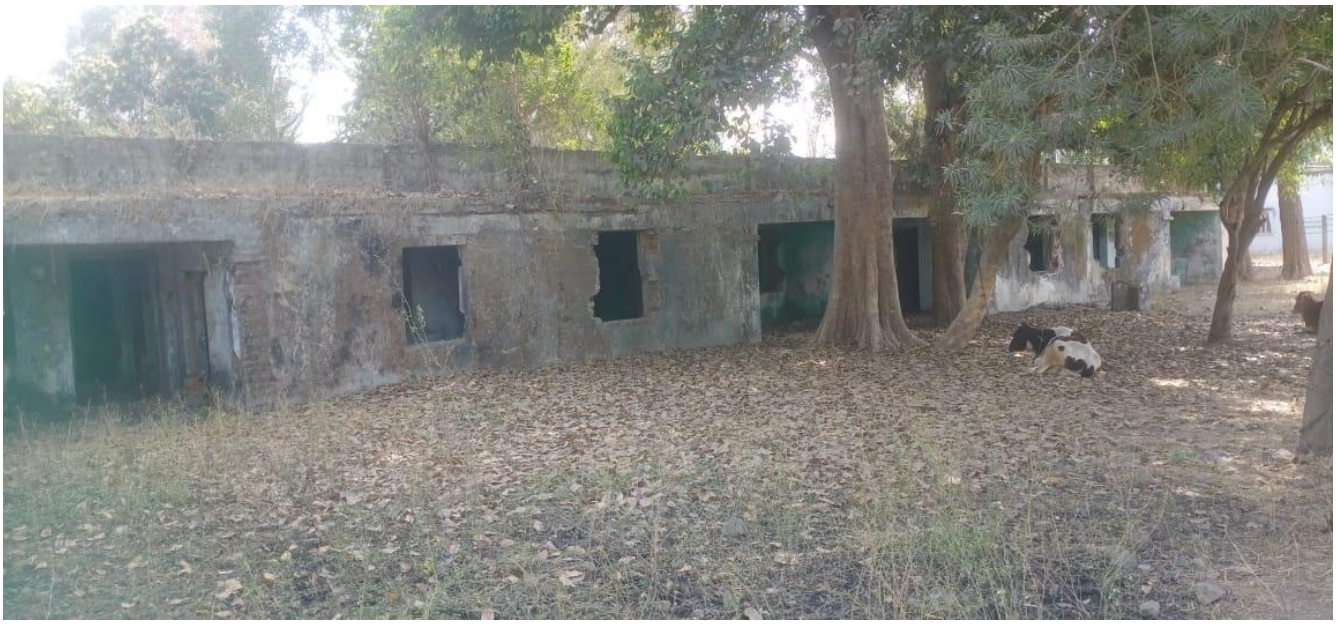

जर्जर हो गया राजहरा के प्रोजेक्ट ऑफिस का आवास. फोटो: मनोज सिंह

निष्कर्ष

तीन महीने के दौरान जब अलग-अलग लोगों से बात की गयी, चाहे वह मजदूर हो या चाहे कर्मचारी चाहे यूनियन लीडर्स, सब का कहना है कि झारखंड जैसे राज्य में कोयले के बिना भविष्य का सोचना भी मुश्किल है. झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोल पर आश्रित है. लोगों की जिंदगी का हर पहलू उससे जुड़ा हुआ है. सबका मानना है कि अभी राज्य में कोयला खत्म नहीं हो सकता है.

उनके कहना है कि आने वाले सालों में जब भी राज्य में कोयले का उत्पादन को कम करने पर बात होगी, तो कर्मचारी, मजदूर, यूनियन नेता सबके साथ बैठक कर सरकार को बात करनी पड़ेगी. विकल्प बताना पड़ेगा. तभी एक सकारात्मक तौर से यह बात आगे बढ़ेगी. नहीं तो लोगों के लिए जीने-मरने की स्थिति भी पैदा हो जायेगी. उनका कहना था कि अगर उनको विश्वास में लिये बिना कोई भी कदम उठाया गया चाहे आज या चाहे 30-40 बाद तो उनको हक के लिए लड़ना पड़ेगा.

उनका कहना था कि जस्ट ट्रांजिशन के लिए दो सबसे जरूरी बात है. पहला कि लोगों को विश्वास में लिया जाये, उनसे बात की जाये और उनके लिए भी विकल्प तैयार की जाये. क्योंकि लोगों ने तो यह भी कहा कि विकल्प सिर्फ उनके लिए ही नहीं, सरकार को भी चाहिए. क्योंकि कोयले से सरकार को हजारों करोड़ राजस्व मिलता है.